डॉ. यादव ने गाजीपुर व बलिया में जनसभाओं को किया संबोधित

भोपाल (काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के शेखपुर में भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय, बलिया जिले के बैरिया में भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा के लोग न भगवान श्रीराम को मानते हैं, न श्रीकृष्ण को मानते हैं, न श्रीमद भागवत गीता को मानते हैं और न ही गाय को मानते हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए आ जाते हैं।

जिस तरह से रावण ने नकली साधु का रूप धारण करके सीता माता का हरण किया था, इसी तरह ये लोग भी नकली भेष बनाकर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। 10-10 मुंह से बोलने वाले घमंडिया गठबंधन का भरोसा नहीं है कि कौन क्या बोलेगा? ये घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन संस्कृति को कोसते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी भरकर अपशब्द कह रहे हैं। भगवान श्रीराम के जन्म के प्रमाणों को मांगने वालों को इस बार जनता सबब सिखाएगी। डॉ. यादव ने कहा कि हम जब भी धर्म की बातें करते हैं तो कांग्रेस और समाजवादियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ये लोग हमको कोसते हैं कि हम धर्म की बातें क्यों कर रहे हैं? ये लोग भगवान श्रीराम पर प्रश्न उठाते हैं, श्रीकृष्ण पर प्रश्न उठाते हैं। भगवान श्रीराम के जन्म के प्रमाण मांगते हैं, लेकिन ये भगवान को नहीं मानते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि कांग्रेस और इसके घमंडिया गठबंधन के लोगों ने भगवान श्रीराम का आमंत्रण भी ठुकराया था। ये लोग भगवान श्रीराम की संस्कृति को मिटाने में लगे हैं। इस बार देश की जनता भी इनको पूरी तरह से ठुकराने वाली है। डॉ. यादव ने कहा कि गाजीपुर में कोई फैक्ट्री नहीं है। उद्योग यहां चलता नहीं है, क्योंकि यहां एक ही परिवार के लूट का उद्योग चलता है। कोई हथियार के बल पर तो कोई पैसों के बल पर लूटता है। आतंक का तांडव मचा रखा है। याद रखना जितना भी तांडव करोगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हर बात का हिसाब होगा। गाजीपुर से लेकर पूरे देश में आतंकवाद था। देश में रहकर पाकिस्तान के लिए नारे लगाते थे। देश का खाते थे और पाकिस्तान के गुणगान गाते थे। उस पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की हिम्मत भाजपा की सरकार ने की है। कांग्रेस का एक परिवार वर्षों से उत्तरप्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व करता रहा है। इनकी कई पीढ़ियां यहां से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन वे क्षेत्र में युवाओं के लिए उद्योग तक नहीं लगवा सके। वे यहां पर सिर्फ मतदाताओं को लूटने का उद्योग चलाते रहे। इन्होंने पहले अमेठी को बर्बाद किया था और अब रायबरेली को भी बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। पिछली बार केरल पहुंचे थे, लेकिन इस बार वहां से भाग आए हैं।

फलोदी सट्टा बाजार के बदलते अनुमान बढ़ा रहे हैं दिलों की धड़कनें

भोपाल (काप्र)।

लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर जहां राजनीतिक गलियारे में गरमा-गर्मी चल रही है, वहीं सट्टा बाजार में भी इसे लेकर जबरदस्त रुझान देखने को मिले हैं। जैसे-जैसे चुनाव परिणाम की तारीख 4 जून नजदीक आ रही है राजस्थान का सबसे चर्चित सट्टा बाजार का आंकलन लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ाने का काम कर रहा है।

फलोदी सट्टा बाजार को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुई है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खासी बढ़त मिलती नजर आई है। संपूर्ण लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तब भी इंडिया गठबंधन को एनडीए से बेहतर स्थिति में दिखलाया गया है। फलोदी सट्टा बाजार के नाम से सोशल मीडिया में जारी एक आंकलन के अनुसार कुल 543 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 346 और मोदी (एनडीए) को 165 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश लोकसभा की 29 सीटों में से इंडिया को 10 और मादी (एनडीए) को 19 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बल्ले-बल्ले होने वाली है। फलोदी सट्टा बाजार का यह रुझान अभी सोशल मीडिया पर वायरल ही हो रहा था कि सट्टा बाजार का अनुमान बदलने का दावा भी सट्टा बाजार के सूत्रों ने करना शुरु कर दिया। इस बदले हुए अनुमान के मुताबिक एक बार फिर साल 2014 और 2019 के आंकड़े रिपीट होने जा रहे हैं। दरअसल, फलोदी सट्टा बाजार के बदले हुए अनुमान की माने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस साल 2014 या साल 2019 जैसी स्थिति में ही रहने वाली है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश की 7 सीटों में जबरदस्त फाईट सट्टा बाजार शो कर रहा है। इसी तरह सट्टा बाजार बीजेपी को देशभर में 280 से 290 सीटों की संभावना जता रहा है, जबकि कांग्रेस को 70 से 85 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सट्टा बाजार का आंकलन भी लोगों को चौंका रहा है। सट्टा बाजार सूत्र बताते हैं कि लोकसभाल चुनाव 2024 के 04 चरण तक फलोदी सट्टा बाजार में 110 करोड़ रुपए दांव पर लगाए जा चुके हैं। पांचवें चरण का मतदान कल 20 मई को होने के बाद दो चरण का मतदान अभी शेष रह जाता है। ऐसे में पूरे लोकसभा चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार में सट्टे का कारोबार करीब 3 सौ करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। जहां तक जीत हार की संभावना का सवाल है तो अगले चरणों के मतदान प्रतिशत को देखते हुए अनुमान एक बार नहीं बल्कि बार-बार बदलते दिख सकते हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन को पिछले चुनावों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में सट्टा बाजार रखता है, जो अपने आप में एनडीए के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

आउटसोर्स कर्मचारियों का घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन 16 जून को

भोपाल (काप्र)। आउटसोर्स कर्मचारी संघ में 16 जून को घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन करने जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायत, अंशकालीन, अल्प वेतन भोगी, चौकीदार, भृत्य, पंप आपरेटर, स्कूलों में अंशकालीन भृत्य, आदिम जाति विभाग में दैनिक मजदूरी, अंशकालीन भृत्य, रसोईया, सफाई कर्मचारी, वाहन चालक, पेशा मोबलाईजर, आयुष में योग प्रशिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में सपोर्ट स्टाफ सहित सभी विभागों के आउटसोर्स, अस्थाई, ठेका कर्मचारी शामिल होंगे।

निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने बताया कि महत्वपूर्ण काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार मात्र 2 से 5 हजार भत्ता दे रही है, इस महंगाई में इतने कम मजदूरी में गुजारा मुश्किल हो रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत भृत्य चौकीदार संघ के अध्यक्ष यशवंत गेडाम, अनिल यादव, अंशकालीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाशंकर पाठक से बातचीत के बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है।

मतगणना के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां, 22 टेबलें तक लगेंगी

भोपाल (काप्र)। लोकसभा चुनाव की चार जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टरों से कहा है कि जिन सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या अधिक है, वहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि परिणाम आने में देरी न हो। मतगणना के लिए 22 तक टेबल लगाई जाएंगी। भिंड, मुरैना सहित संवेदनशील लोकसभा सीटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। चार जून को सभी 52 जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी।

मतगणना के लिए न्यूनतम सात और अधिकतम 14 टेबल लगाने का प्रावधान है। इससे अधिक टेबल लगाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होती है। जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना का कार्य तेजी से पूरा करने के लिए अधिक टेबल लगाने की अनुमति मांगते हैं। इस बार भी 22 टेबल लगाने की अनुमति मांगी गई थी, जो आयोग ने दे दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि टेबलों की संख्या का निर्धारण स्थान और कर्मचारियों की व्यवस्था पर निर्भर करता है। एक गणना टेबल पर तीन कर्मचारी लगते हैं। साथ ही जितने प्रत्याशी होते हैं, उनके अभिकर्ता रहते हैं। इतने लोगों की व्यवस्था को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा टेबलों की संख्या प्रस्तावित की जाती है। जिलों में मतगणना के लिए कर्मचारी चिन्हित कर लिए गए हैं। इन्हें एक सप्ताह में गणना संबंधी प्रावधानों का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों से दिलाया जाएगा।

निगरानी के लिए अलग से रहेंगे पर्यवेक्षक: डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग से टेबल लगाई जाएगी। इस कार्य की निगरानी के लिए अलग से पर्यवेक्षक रहेंगे। प्रत्याशी डाक मतपत्र की गणना के लिए अलग से अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। इस बार 75 हजार से अधिक सेवा मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी किए गए हैं।

कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों को भाजपा में मिलेगा अपनापन

भोपाल (काप्र)।

लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कांग्रेस को पीठ दिखाने वाले दगाबाज नेताओं को अब भाजपा अपनापन देने पर विचार कर रही है। पार्टी की मुख्यधारा से जोडने् के लिए अब इन्हें हर बैठक और गतिविधि से जोड़ा जाएगा। इनमें से कुछ नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। चुनावी नतीजे आने के बाद इस प्रक्रिया पर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन प्रदेश की इस सियासी गतिविधि पर पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही काम करेगा।

गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस के हाथ से सरकार खींच ले जाने के अगुआ बने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा पद और कद से नवाज चुकी है। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा के रास्ते केंद्र सरकार का सदस्य भी बनाया और इस सरकार में महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री भी बनाया गया। इस लोकसभा चुनाव में सिंधिया को मैदान दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस चुनाव में जीत के बाद उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

बड़ी संख्या में कांग्रेसी आए भाजपा में: लोकसभा चुनाव के दौरान तेजी से चले घटनाक्रम में बड़ी तादाद में कांग्रेस की टूट के हालात बने थे। भाजपा और कांग्रेस इस पलायन को लेकर अलग अलग आंकड़े पेश करते रहे हैं। लेकिन पलायन के बाद नई पार्टी और नए लोगों के साथ जा बैठे पुराने पूर्व कांग्रेसियों को अब अपने वजूद पर संकट नजर आने लगा है। भाजपा नेतृत्व ने नई आमद की इसी बेचैनी को भांपते हुए नई रणनीति बनाई है। इसके तहत अब कांग्रेस से आए नेताओं को भाजपा की मुख्यधारा से जोडने् की तैयारी की जा रही है। पार्टी ने जिला और मंडल अध्यक्षों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं। इन्हें कहा गया है कि नई आमद को हर बैठक और पार्टी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है।

मिलेगी नई भूमिका: कांग्रेस से पलायन करके भाजपा में आए कई नेता अपनी पूर्व पार्टी में कद, पद, ओहदा और सम्मान रखते थे। भाजपा ने इन लोगों को उनका खोया सम्मान लौटाने की भी रणनीति बनाई है। तय किया गया है कि ऐसे सभी नेताओं को उनके सामर्थ्य और कार्यशक्ति के लिहाज से भूमिका दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर ही काम किया जाएगा। इससे पहले इस बात पर भी सहमति बन चुकी है कि कांग्रेस छोडक़र भाजपा में आए विधायकों को प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ऐसे विधायकों की गिनती करीब चार के आसपास है।

पचास हजार अंशकालीन कर्मचारियों को नौ माह से नहीं मिला वेतन

भोपाल (काप्र)।

प्रदेश के शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य दर्जनों विभागों में कार्यरत 50 हजार अंशकालीन कर्मचारियों को पिछले 9 माह से वेतन नहीं मिला है। मप्र कर्मचारी मंच ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल वेतन भुगतान करने की मांग की है।

मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री अंशकालीन कर्मचारियों को संबल योजना से जोडने् का निर्णय लिया हैं, लेकिन अंशकालीन कर्मचारी पिछले 9 माह से वेतन के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। अधिकारियों से वेतन मांगने पर अधिकारी बजट न होने का बहाना बताकर अंशकालीन कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने से मना कर देते हैं। अंशकालीन कर्मचारियों ने जिला कलेक्टरों को भी ज्ञापन सौंप कर वेतन भुगतान करने की मांग की, लेकिन कलेक्टरों ने मात्र आश्वासन देकर अंशकालीन कर्मचारियों को भूखे रहने पर मजबूर कर दिया है। पांडे ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण अंशकालीन कर्मचारी के बच्चों के स्कूल से नाम काटे जा रहे हैं। राशन न होने के कारण उनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इस कारण प्रदेश के 50 हजार अंशकालीन कर्मचारी परिवार में राज्य सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया है। यदि राज्य सरकार ने अंशकालीन कर्मचारियों को एक सप्ताह के अंदर वेतन भुगतान करने की व्यवस्था नहीं की तो प्रदेश भर के अंशकालीन कर्मचारी आचार संहिता की बाद भोपाल के अंबेडकर जयंती में भूख हड़ताल आंदोलन करेंगे।

व्यंग्य पुरोधा शरद जोशी को समर्पित गोष्ठी

व्यंग्य की अक्षय-अविरल धारा थे शरद

भोपाल (काप्र)। अभा साहित्य परिषद की मासिक गोष्ठी व्यंग्य के सफल हस्ताक्षर शरद जोशी को समर्पित रही, जिसमें उनके व्यंग्यों का पाठ हुआ।

गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर नुसरत मेहदी ने कहा कि परिषद् का उद्देश्य रहता है कि पठन ,पाठन व श्रवण होता रहे। उन्होनें अध्यक्षीय उद्बोधन में अध्यक्ष व्यंग्य पढ़ा। जिसमें अध्यक्ष के प्रकार का मजेदार विस्तृत वर्णन किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि रमेश व्यास शास्त्री ने कहा कि शरद जी के व्यंग्य आज भी समाज में व्याप्त है। उन्होनें शरद जी का व्यंग्य - चोर !चोर! लेखक! लेखक पढ़ा। गोष्ठी में बीज वक्तव्य देते हुए परिषद् महामंत्री सुनीता यादव ने बताया कि- जोशी जी की रचनात्मकता अपने जीवन के आखिरी पल तक बढ़ती ही चली गई। वे चुके नहीं। वे व्यंग्य की अक्षय अविरल धारा थे, उनके लिए व्यंग्य लिखना सांस लेने जैसा जरूरी और सहज था। वे जिन मूल्यों के लिए लड़े उन्ही मूल्यों और शर्तों पर जीते रहे, वे समझौता कर लेते तो शरद जोशी न रह पाते। कार्यक्रम में शीला मिश्रा ने व्यंग्य पढ़ा ऊपर उठने की मुसीबत, अनीता सिंह ने व्यंग्य पढ़ा- इस वसंत में भोपाल जया आर्य ने व्यंग्य पढ़ा- लंच के बाद भारत, सुधा दुबे ने व्यंग्य पढ़ा - प्रभु हमें डाक्ट्रेट से बचाना, अनूप धामने ने प्रसिद्ध व्यंग्य गॉडेस लक्ष्मी याने पैइसा का गॉडेस पढ़ा।

गोष्ठी में स्वागत वक्तव्य परिषद के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी साहित्यार्थी ने दिया ,कार्यक्रम का संचालन नीता सक्सेना ने किया सरस्वती वंदना श्रद्धा यादव ने प्रस्तुत की और आभार श्रीराम माहेश्वरी ने किया। कार्यक्रम में लेखिका संघ की अध्यक्ष डॉ. कुमकुम गुप्ता, साहित्यकार श्रीराम माहेश्वरी , गजलकार कमलेश गुल, कवयित्री लता स्वरांजलि, सुनीता केसवानी आदि साहित्यकार उपस्थित रहे।

न्यूनतम वेतन, कामगार प्रशिक्षण, कौशल विकास और सुरक्षा पर संगोष्ठी

भोपाल (काप्र)। एचआरडी फोरम मध्यप्रदेश की मासिक संगोष्ठी मंडीदीप स्थित टेफे मोटर्स एंड ट्रेक्टर परिसर में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अजय सिन्हा वाइस प्रेसिडेंट टेफे मोटर्स ने की। इसमें 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फोरम के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को औद्योगिक, वाणिज्य एवं तकनीकी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगो में छात्रों को अधिकतम रोजगार मिले। इस पर चर्चा करें। फोरम के उपाध्यक्ष ए.के सिंघल ने श्रम कानूनों के सरलीकरण पर जोर दिया। अजय सिन्हा ने मानव संसाधान और मानवीय संबंध विषय पर व्याख्यान दिया। जी.के छिब्बर ने न्यूनतम वेतन की विसंगति पर चर्चा की। संगोष्ठी में एच ई जी, वर्धमान, भास्कर इंडस्ट्रीज, अनंत और नाहर स्पिनिंग टैफे मोटर्स नोबल हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल के अधिकारी एवं एचआरडी विशेषज्ञ एन. के. छिब्बर, आरजी दिवेदी, डॉ. इफ्तखार अली, विनोद चोरे, शैलेश मिश्रा, आदित्य गर्ग मनोज मोदी ने भी विचार प्रगट किए। आभार प्रदर्शन सुरेश कुमार ने किया।

स्पेशल खबर हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब...

किस नियम से किया 13 प्रतिशत परीक्षा परिणाम को होल्ड

भोपाल (काप्र)।

जबलपुर हाई कोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा 87-13 फार्मूले के आधार पर पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेट) का परिणाम जारी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने एमपीपीएससी के चेयरमैन से 13 प्रतिशत रिजल्ट होल्ड किए जाने के संबंध में जवाब मांगा है।

याचिका पर अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। रीवा निवासी शिवेन्द्र कुमार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। उसके लिए सेट एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। एमपीपीएससी ने परीक्षा का आयोजन करवाया हुए रिजल्ट जारी किया। आयोग ने सेट का रिजल्ट 87-13 के अनुपात में जारी किया। आयोग ने सामान्य व ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत रिजल्ट रोक दिए, जिसके कारण कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। याचिका में कहा गया था कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से 13 प्रतिशत रिजल्ट रोकने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आयोग ने मनमाने तरीके से 13 प्रतिशत रिजल्ट को होल्ड किया है। आयोग द्वारा असि. प्रोफेसर व लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने आयोग के अध्यक्ष से पूछा है कि किस नियम के तहत 13 प्रतिशत रिजल्ट को होल्ड किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने पैरवी की।

विज्ञापन के बाद जारी हुआ बीपीएल कार्ड मान्य नहीं

जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि नियुक्ति विज्ञापन के बाद जारी हुआ बीपीएल कार्ड मान्य नहीं है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने उक्त आदेश के साथ बीपीएल कार्ड होने के कारण महिला अभ्यर्थी को दस अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता सविता की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसने निमाड़ी जिले के काका देही ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आवेदन किया था। अनावेदक शांति कुशवाहा को बीपीएल कार्ड का लाभ प्रदान करते हुए दस अंक प्रदान कर दिए। याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन जारी होने की तिथि पर उपलब्ध दस्तावेज का अभ्यर्थियों का लाभ मिलता है। अनावेदक महिला के पास विज्ञापन जारी होने की तिथि तक बीपीएल कार्ड नहीं था। इसलिए उसे अतिरिक्त दस अंक नहीं मिलने चाहिए थे। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि नियुक्ति के लिए 16 मार्च 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था और आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। अनावेदिका को 24 मार्च 2021 को बीपीएल कार्ड जारी हुआ था। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए।